आपका हमें संरक्षण प्राप्त हो । एक वहां पर उषा रेक्टीफायर्ज है । किसी तरह से उसने अपना नाम अब बदल दिया है मालिका स्टील्ज कर दिया है। और 35 हजार रुपए के हिसाब से तय हुआ था कि लोगों की जो जमीन ली गई है उनको उसके लिए उसका कंपेंसेशन देगी, लेकिन उतना रुपया न दे करके सिर्फ करीब सवा करोड़ रुपया उसने अलाट किया है जिसमें कि वह 50 प्रतिशत भी नहीं है जितना कि वहां पर कंपेंसेशन बंटना है । आज लोगों में इसका बहुत भयानक असंतोष है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भी नीयत साफ नहीं है और आई.डी.बी.आई. के लोन की प्रतीक्षा वह कर रहे हैं ।

जिसमें कि 120 करोड़ उनको मिलना है । लेकिन, ऐसा सुनने में आता है कि उस लोन को लेने के बाद ही वह वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं ।

माननीय महोदय, करीब पिछले दो सालों में छोटी-बड़ी 26 यूनिटें वहां बंद हो गई हैं, जिसमें कि चार-पांच, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ज्वाइंट वेंचर से है, पी-सी.एफ. कोल्ड स्टोरेज, पी.सी.एफ. दाल मिल और पी.सी.एफ. राइस मिल, इस तरह कोई छोटी-बड़ी 26 यूनिट हैं, जो पिछले कुछ सालों में बंद हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आज वहां पर राजनीतिक संरक्षण कमजोर होने के बाद वहां से लोग अपना पैसा इकट्ठा करके, यूनिट बंद करके या तो शिफ्ट करना चाहते हैं या वहां से जाने के चक्कर में हैं, जिनसे वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिला हुआ था, क्षेत्र का विकास हुआ था । तो मैं इस ज्वलंतनीय लोक महत्व के सवाल के माध्यम से आपका संरक्षण चाहते हुए आपका निर्देश चाहता हूं कि आप संबंधित विभागों को निर्देशित करें कि जो यूनिट वहां हैं, जिनको उसी क्षेत्र की वजह से तमाम सारा पैसा मिला, उस क्षेत्र के विकास में तमाम सारे लोगों ने आशाएं हुई, सैकड़ों-हजारों लोगों को रोजगार मिला और इन यूनिट के न रहने से उनको तमाम बाधाएं होने वाली हैं, उन यूनिट को वहां से न हटाया जाए । यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत चिन्ताजनक विषय है । सुबह भी इसी से मिलाजुला प्रश्न गुरूदास दासगुप्त जी ने उठाया था । मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं और उनके मंत्रालय से इसका संबंध भी है, तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर अपना आश्वासन दें कि सरकार इसको देख रही है ताकि वहां कम से कम जो लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं या वहां से हटाए जा रहे हैं उनको संरक्षण मिले ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : स्पेशल मेंशन में यह सवाल आप मत उठाइए । सरकार तक तो यह बात पहुंच ही जाएगी । श्री मुथु मनी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मंत्री जी शायद रिएक्ट कर दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बात यह है कि मैं ही उनको एलाऊ नहीं कर रहा हूं ।

Need to extend the scope of reservation for Socially and Educationally backward Classes

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): I draw the attention of the Government towards Article 340 of the Constitution to impress upon the necessity to provide adequate reservation to the Backward Classes in Educational Institutions without further delay. As a nationalist our late beloved leader Dr. M. G. R. was the first Chief Minister in India to raise the percentage of reservations to 50 for the Backward Classes in Education as well as job opportunities. Our Hon'ble Chief Minister Dr. Puratchithalavi is also committed to the welfare of the

downtrodden. That is why a Resolution was passed in the recent historic AIADMK Conference at Madurai urging the Centre to provide reservation to Backward Classes in Educational Institutions and also in Government job opportunities.

But the statement by the hon. Welfare Minister Shri Sitaram Kesari on 10th August, 1992 on the Floor of this regarding reservation to SEBCs is inadequate and has raised more questions than it answered. The vital issue of porviding reservation to Backward Classes in Educational Institutions has not been referred to even. I am at a loss to understand as to how can you get eligible candidates from the Backward Classes unless you reserve seats for them in Educational Institutions. You call them Socially and Educationally Backward but do not provide them Educational Opportunities. I ask how the Government is going to liberate them from Educational Backwardness? For example, we have been having reservation for SC/ST in Educational Institutions as well. Yet it is a fact that eligible SC/ST Candidates are not found for various posts. There is a huge backlog of vacancies reserved for SC/ST. The Central Government could not fill these vacancies so far in spite of Special Recruitment Drives. But what is surprising is the failure of the Centre to learn lessons from the past.

Article 340 provides for removing the difficulties faced by the Socially and Educationally Backward Classes and to improve their condition. Therefore, I say very assertively that attempt should not be made to whittle down this provision of the Constitution. Any reservation jobs without reservation in Educational Institution will not bring about any change in their condition. Unless they are Educationally liberated, Social liberation cannot take place.

As such the Government would do well to brood over this serious matter before deciding anything in haste. Even the proposed 27 per cent reservation is not sufficient keeping in view the huge chunk of Backward Classes in the country. At least 50 per cent reservation should be provided to them in both educational institutions and Government offices. I warn the Centre not to give in to the pressures from the people belonging to privileged classes. Therefore, I demand that 50 per cent seats should be reserved in educational institutions as also in job opportunities for the backward classes who have remained oppressed for hundred of years.

Need to issue a Commemorative Stamp to honour the Great Freedom Fighter Shri Achyut Patvardhan

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी पिछली 8 अगस्त को सारा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो 8 अगस्त, 1942 को "करो या मरो" का नारा दिया था, उसकी स्वर्ण जयंती मना रहा है और इसी संदर्भ में यह समारोह साल भर तक चलेगा और जो देश के स्वतंत्रता सैनानी हैं राष्ट्रीय संग्राम के, उनका राष्ट्र आदर भी कर रहा है और उसके ठीक 4 या 5 दिन पूर्व वाराणसी में श्री अच्युत पटवर्धन का निधन हो गया। अच्युत जी 1930 के असहयोग आन्दोलन में, 1930 के सत्याग्रह में और सन् 1942 का जो गांधी का "भारत छोड़ो" आन्दोलन था, उसमें थे। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो चार या पांच लोग जो भूमिगत हो गए थे, जिन्होंने भूमिगत होकर आन्दोलन चलाया था— लोकनायक जय प्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया और खुशी का विषय है कि अरूणा जी आज हमारे बीच में हैं या ऊषा जी बम्बई वाली और अच्युत पटवर्धन, इन लोगों ने भूमिगत आन्दोलन का नेतृत्व किया और देश की आजादी के बाद वे सत्ता की राजनीति से दूर रहे। वे शिक्षा-शास्त्री भी थे और उन्होंने समाज-सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और बनारस में कृष्णामूर्ति फाउंडेशन उन्होंने वहां पर स्थापित किया